जहाज रिसाइक्लिंग में भारत बना नंबर वन

अलंग-सोसिया शिप रिसाइक्लिंग क्लस्टर ने बढ़ाई भारत की ताकत

नई दिल्ली, 11 अगस्त जहाज रिसाइक्लिंग के क्षेत्र में भारत ने वैश्विक स्तर पर बड़ी उपलब्धि हासिल की है. वर्ष 2025 में भारत दुनिया का सबसे बड़ा जहाज रिसाइक्लिंग राष्ट्र बनकर उभरा है.

आधिकारिक फैक्टशीट के अनुसार, वैश्विक जहाज रिसाइक्लिंग बाजार में भारत की हिस्सेदारी 2024 के 30.1 प्रतिशत से बढ़कर 2025 में 35.4 प्रतिशत तक पहुंच गई है. यह बढ़ोतरी न केवल भारत की समुद्री उद्योग क्षमता को दर्शाती है, बल्कि पर्यावरण अनुकूल पुनर्चक्रण और संसाधनों के बेहतर उपयोग की दिशा में देश की प्रगति को भी रेखांकित करती है. आंकड़ों के मुताबिक, भारत में जहाज रिसाइक्लिंग की मात्रा वर्ष 2024 में 1.86 मिलियन ग्रॉस टन (जीटी) थी, जो 2025 में बढ़कर 2.99 मिलियन जीटी हो गई. यानी एक साल के भीतर इस क्षेत्र में करीब 60 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई. इस उपलब्धि के पीछे गुजरात स्थित अलंग-सोसिया शिप रिसाइक्लिंग क्लस्टर की महत्वपूर्ण भूमिका रही है.

गुजरात का अलंग-सोसिया शिप रिसाइक्लिंग क्लस्टर दुनिया के सबसे बड़े जहाज पुनर्चक्रण केंद्रों में शामिल है. भारत में होने वाली कुल जहाज रिसाइक्लिंग गतिविधियों में इस क्लस्टर की हिस्सेदारी लगभग 98 प्रतिशत है.

> भारत अब अपनी जहाज रिसाइक्लिंग क्षमता को लगभग दोगुना करने की योजना पर काम कर रहा है. सरकार का लक्ष्य इसे बढ़ाकर करीब 9 मिलियन लाइट डिस्प्लेसमेंट टन तक पहुंचाना है. इसके लिए अलंग शिप रिसाइक्लिंग यार्ड के विस्तार और विकास की योजना बनाई गई है.गुजरात के अलावा देश में अन्य स्थानों पर भी जहाज रिसाइक्लिंग गतिविधियां संचालित होती हैं. इनमें अमर आयरन उद्योग, कोलकाता और स्टील इंडस्ट्रियल्स केरल लिमिटेड, केरल जैसे केंद्र शामिल हैं.सरकार के अनुसार, मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 के तहत भारत ने दुनिया का अग्रणी जहाज रिसाइक्लिंग राष्ट्र बनने का लक्ष्य तय समय से पांच साल पहले हासिल कर लिया है.

जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में निजी निवेश बढ़ेगा

जैव प्रौद्योगिकी उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने पर जोर

स्टार्टअप को 200 करोड़ रुपये तक वित्तीय सहायता का प्रावधान

नयी दिल्ली, 11 अगस्त भारत के जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में निजी निवेश और उद्योग की भागीदारी बढ़ाने की दिशा में सरकार ने प्रयास तेज कर दिए हैं.

केंद्रीय विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) जितेंद्र सिंह ने उद्योग जगत से देश के जैव प्रौद्योगिकी इकोसिस्टम में मजबूत भागीदारी निभाने की अपील की है. उन्होंने स्वदेशी जैव प्रौद्योगिकी उत्पादों और तकनीकों को बढ़ावा देने, निजी निवेश आकर्षित करने तथा अनुसंधान एवं विकास से तैयार नवाचारों को तेजी से बाजार तक पहुंचाने पर जोर दिया नई दिल्ली में जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में उन्होंने जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में निवेश, उद्योग की भागीदारी और बाजार के अवसरों को बढ़ाने से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की.

उन्होंने कहा कि स्वदेशी तकनीक, उद्योग और निवेशकों के बीच मजबूत संपर्क स्थापित होने से प्रयोगशाला में विकसित नवाचारों को व्यावसायिक उत्पादों में बदलने की प्रक्रिया तेज की जा सकती है. बैठक में 5200 करोड़ रुपये के बीआईआरएसी अनुसंधान, विकास एवं नवाचार कोष के क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान दिया गया.

दुबई के बाजार में पहुंचेगा त्रिपुरा का सरसों वाला शहद

एपीडा की पहल से किसानों को मिला अंतरराष्ट्रीय बाजार तक सीधा रास्ता

विदेशी खरीदारों से जुड़ेंगे मधुमक्खी पालक, बढ़ेगी आय की संभावना

अगरतला, 11 अगस्त त्रिपुरा के किसानों और मधुमक्खी पालकों के लिए एक नई उम्मीद की शुरुआत हुई है. राज्य से पहली बार सरसों के शहद की खेप दुबई भेजी गई है. एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी (एपीडा) के अनुसार, त्रिपुरा से 1 मीट्रिक टन सरसों के शहद का निर्यात संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के दुबई बाजार के लिए किया गया है.

यह कदम राज्य के छोटे किसानों और मधुमक्खी पालकों को अंतरराष्ट्रीय बाजार से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है.दुबई जैसे बड़े वैश्विक बाजार में भारतीय कृषि उत्पादों की बढ़ती मांग के बीच त्रिपुरा के शहद को नई पहचान मिलने की संभावना है. अभी तक कई छोटे किसान और मधुमक्खी पालक अपने उत्पादों को स्थानीय बाजारों तक ही सीमित रखते थे. लेकिन अब विदेशी बाजार तक सीधी पहुंच मिलने से उन्हें बेहतर कीमत, नए खरीदार और अतिरिक्त आय के अवसर मिल सकते हैं.

यह पहली निर्यात खेप डेरगांग फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गनाइजेशन (एफपीओ) से जुड़ी है. एफपीओ के माध्यम से जुड़े किसानों और मधुमक्खी पालकों को उम्मीद है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में पहुंच बनने के बाद शहद उत्पादन को बड़े स्तर पर बढ़ावा मिलेगा. इससे न केवल किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, बल्कि राज्य में मधुमक्खी पालन को एक संगठित व्यवसाय के रूप में विकसित करने में भी मदद मिलेगी.

सरकार का मानना है कि कृषि उत्पादों के निर्यात से किसानों को स्थानीय मंडियों से आगे बढ़कर वैश्विक खरीदारों तक पहुंचने का अवसर मिलता है. खासतौर पर शहद जैसे प्राकृतिक उत्पादों की विदेशों में अच्छी मांग है. भारतीय शहद अपनी गुणवत्ता और प्राकृतिक स्वाद के कारण कई देशों में पसंद किया जाता है.त्रिपुरा में सरसों की खेती के साथ-साथ मधुमक्खी पालन की अच्छी संभावनाएं हैं. सरसों के फूलों से तैयार शहद अपने विशेष स्वाद और गुणवत्ता के लिए जाना जाता है. अब दुबई के बाजार में पहुंचने के बाद इसकी मांग बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है.

> एपीडा लगातार कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किसानों, एफपीओ और निर्यातकों के बीच समन्वय का काम कर रहा है. इसके तहत स्थानीय उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने की कोशिश की जा रही है .अगर त्रिपुरा के शहद को लगातार विदेशी बाजार मिलते रहे तो इससे राज्य में मधुमक्खी पालन को बढ़ावा मिलेगा और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर भी पैदा हो सकते हैं.

ईपीएफओ में हायर पेंशन के 15 लाख दावे

नयी दिल्ली, 11 अगस्त कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के सदस्यों के लिए हायर पेंशन को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है. केंद्र सरकार ने संसद में बताया कि ज्यादा वेतन के आधार पर अधिक पेंशन पाने के लिए अब तक 15.24 लाख से अधिक दावे प्राप्त हो चुके हैं. इनमें से 5 अगस्त 2026 तक केवल 11,595 दावे लंबित थे.

सरकार के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के 4 नवंबर 2022 के फैसले के बाद हायर पेंशन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया है और बड़ी संख्या में पात्र सदस्यों के मामलों का निपटारा किया जा चुका है.श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने लोकसभा में लिखित जवाब में बताया कि प्राप्त दावों के आधार पर अब तक 1,49,806 पेंशन भुगतान आदेश जारी किए जा चुके हैं.

हायर पेंशन विकल्प के तहत पात्र कर्मचारियों को निर्धारित पेंशन योग्य वेतन सीमा के बजाय वास्तविक मूल वेतन के आधार पर पेंशन में अधिक योगदान करने का विकल्प मिलता है. इसके बदले सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाली मासिक पेंशन बढ़ सकती है.

धूत ट्रांसमिशन की मजबूत छलांग

ईवी बाजार से बढ़ेंगी उम्मीदें

मुंबई, 11 अगस्त धूत ट्रांसमिशन लिमिटेड का ?3,066.89 करोड़ का आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) 10 अगस्त 2026 को खुलने जा रहा है. इसके लिए प्रति इक्विटी शेयर 829-871 का मूल्य दायरा तय किया गया है. आईपीओ 12 अगस्त को बंद होगा.

इसमें 1,400 करोड़ का नया निर्गम और करीब 1,666.89 करोड़ की बिक्री पेशकश (ओएफएस) शामिल है. आईपीओ से पहले कंपनी ने 72 एंकर निवेशकों को 871 प्रति शेयर की दर से 1,05,42,657 शेयर आवंटित कर 918.27 करोड़ जुटाए हैं. एंकर आवंटन में घरेलू म्यूचुअल फंडों की हिस्सेदारी 46 योजनाओं के माध्यम से 61.27% रही, जबकि जीवन बीमा कंपनियों और पेंशन फंडों की हिस्सेदारी 8.74% रही. एंकर बुक में एसबीआई म्यूचुअल फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, ब्लैकरॉक, अबूधाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस और एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस जैसे निवेशक शामिल रहे.

धूत ट्रांसमिशन के आईपीओ को लेकर ब्रोकरेज कंपनियों की प्रतिक्रिया भी broadly सकारात्मक रही है. आनंद राठी, चॉइस सिक्योरिटीज, आईसीआईसीआई डायरेक्ट, कुंवरजी वेल्थ सॉल्यूशंस, स्वास्तिका सिक्योरिटीज, वेंचुरा सिक्योरिटीज, बीपी इक्विटीज और सुशील फाइनेंस ने निवेशकों को इस निर्गम में निवेश की सलाह दी है. धूत ट्रांसमिशन की निवेश कहानी का मुख्य आधार ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के क्षेत्र में उसकी मजबूत स्थिति है. कंपनी वायरिंग हार्नेस, सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर, ऑटोमोटिव स्विच और बैटरी पैक बनाती है. इसके उत्पाद पारंपरिक आंतरिक दहन इंजन (आईसीई) के साथ-साथ इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए भी उपयोग किए जाते हैं. वायरिंग हार्नेस को वाहन का विद्युत 'नर्वस सिस्टम' कहा जा सकता है. यह तारों, केबल, कनेक्टर और टर्मिनल का ऐसा नेटवर्क होता है, जो वाहन के विभिन्न हिस्सों के बीच बिजली और इलेक्ट्रॉनिक संकेत पहुंचाता है.

> वित्त वर्ष 2025-26 में भारत के दोपहिया वायरिंग हार्नेस बाजार में धूत ट्रांसमिशन की हिस्सेदारी 37.58% रही और वह शीर्ष दो कंपनियों में शामिल रही. वहीं, तिपहिया वाहनों के बाजार में उसकी हिस्सेदारी 70% से अधिक रही, जिससे वह इस क्षेत्र की बाजार अग्रणी कंपनी बन गई. दोपहिया और तिपहिया वाहनों को मिलाकर कंपनी की कुल बाजार हिस्सेदारी 41.03% रही.

कच्चा तेल 130 डॉलर पार जा सकता है

मध्य-पूर्व तनाव, आपूर्ति संकट और ओपेक+ के फैसलों से कीमतों में तेजी

नयी दिल्ली, 11 अगस्त मध्य-पूर्व में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव के बीच कच्चे तेल की कीमतों में तेज उतार-चढ़ाव जारी है. विशेषज्ञों का अनुमान है कि आने वाले महीनों में अगर आपूर्ति संबंधी संकट और गहराता है तो डब्ल्यूटीआई क्रूड की कीमत 130 डॉलर प्रति बैरल के पार जा सकती है.

इसका सीधा असर भारत पर भी पड़ सकता है, क्योंकि देश अपनी कच्चे तेल की जरूरत का बड़ा हिस्सा आयात करता है. ऐसे में अंतरराष्ट्रीय बाजार में लंबे समय तक कीमतें ऊंची रहने पर पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर भी दबाव बढ़ सकता है. इंटेलिसिस वेंचर्स के संस्थापक और सेबी पंजीकृत शोध विश्लेषक अमित सुरेश जैन के अनुसार, मौजूदा समय में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी के पीछे तीन प्रमुख कारण हैं. इनमें भू-राजनीतिक तनाव, ओपेक+ के आपूर्ति संबंधी फैसले और वैश्विक मांग शामिल हैं. इनमें सबसे बड़ा कारण फिलहाल मध्य-पूर्व का तनाव माना जा रहा है. हॉर्मुज जलडमरूमध्य के बंद होने से वैश्विक तेल आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित हुई है. यह मार्ग अंतरराष्ट्रीय तेल व्यापार के लिए बेहद महत्वपूर्ण है.

शेयर बाजारों में गिरावट सेंसेक्स 388 अंक लुढ़का

मुंबई, 11 अगस्त विदेशों से मिले मिश्रित संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजारों में मंगलवार को बिकवाली हावी रही और बीएसई का सेंसेक्स 388 अंक लुढ़क गया. सेंसेक्स में सुबह से ही गिरावट रही. यह करीब 33 अंक नीचे 78,509.77 अंक पर खुला और पूरे दिन लाल निशान में रहा. एक समय यह करीब 494 अंक गिर गया था. अंत में 388.19 अंक (0.49 प्रतिशत) लुढ़ककर 78,154.25 अंक पर बंद हुआ. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी-50 सूचकांक 112.10 अंक यानी 0.46 प्रतिशत नीचे 24,471.70 अंक पर रहा.

महाप्रबंधक पांडेय ने रेलखंड का किया निरीक्षण

अहमदाबाद, 11 अगस्त पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक रामाश्रय पांडेय ने आज दिनांक 11.08.2026 को अहमदाबाद मंडल के हिम्मतनगर-खेड़ब्रह्मा रेलखंड का निरीक्षण किया. इस दौरान अहमदाबाद मंडल के मंडल रेल प्रबंधक श्री वेद प्रकाश सहित मंडल के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे.

निरीक्षण के दौरान महाप्रबंधक ने रेल परिचालन की सुरक्षा, यात्री सुविधाओं, रेलवे परिसंपत्तियों के रखरखाव तथा विभिन्न विकास परियोजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की. महाप्रबंधक श्री रामाश्रय पांडेय के हिम्मतनगर रेलवे स्टेशन पहुंचने पर अहमदाबाद मंडल के मंडल रेल प्रबंधक श्री वेद प्रकाश द्वारा उनका आत्मीय स्वागत किया गया.

इसके पश्चात महाप्रबंधक एवं मंडल रेल प्रबंधक ने हिम्मतनगर से खेड़ब्रह्मा रेलवे स्टेशन तक विंडो ट्रेलिंग के माध्यम से रेलखंड का निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान उन्होंने रेलवे ट्रैक, लेवल क्रॉसिंग, पॉइंट्स एवं क्रॉसिंग्स सहित विभिन्न आधारभूत संरचनाओं का विस्तृत अवलोकन किया. उन्होंने रेल पथ की स्थिति, परिचालन दक्षता तथा संरक्षा मानकों का आकलन करते हुए संबंधित अधिकारियों को संरक्षा एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक निर्देश दिए. साथ ही रेलखंड पर यात्री सुविधाओं एवं सुरक्षित एवं सुचारू रेल संचालन के लिए आवश्यक व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई. खेड़ब्रह्मा स्टेशन पर निरीक्षण एवं तिरंगा यात्रा खेड़ब्रह्मा रेलवे स्टेशन पहुंचने पर महाप्रबंधक श्री रामाश्रय पांडेय एवं मंडल रेल प्रबंधक श्री वेद प्रकाश ने स्टेशन का विस्तृत निरीक्षण किया.

समाचार विशेष

सज्जाद लोन को त्रेहगाम में चुनौती?

श्रीनगर. हुर्रियत के पूर्व नेता बिलाल गनी लोन ने अपने गृह निर्वाचन क्षेत्र त्रेहगाम से अगला विधानसभा चुनाव लड़ने का संकेत दिया है. इसके साथ ही उन्होंने अपने भाई और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद लोन को सीधी और कड़ी चुनौती देने का ऐलान किया है, जो उसी जिले के हंदवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से चुने गए विधायक हैं.

बिलाल गनी लोन ने त्रेहगाम गांव में आयोजित एक जनसभा के दौरान मुख्यधारा की चुनावी राजनीति में आने का खुला संकेत दिया. त्रेहगाम गांव जेकेएलएफ के संस्थापक और पहले आतंकवादी कमांडर मकबूल भट का गृहनगर है, जिसे 11 फरवरी 1984 को तिहाड़ जेल में फांसी दी गई थी.

उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के करालपोरा इलाके में अपने पैतृक गांव दर्द हरई में एक जनसभा को संबोधित करते हुए बिलाल ने कहा कि बदलते राजनीतिक माहौल में नेताओं के लिए ईमानदारी और जनसेवा बनाए रखना जरूरी है.

सच्चाई, ईमानदारी और जवाबदेही पर आधारित राजनीति के लिए जनता का समर्थन मांगते हुए, लोन ने कहा कि उनकी राजनीतिक यात्रा जनसेवा और पारदर्शी नेतृत्व पर केंद्रित रहेगी. अपने दिवंगत पिता अब्दुल गनी लोन की सलाह को याद करते हुए उन्होंने कहा कि राजनीति को हमेशा सेवा और समर्पण के रूप में देखा जाना चाहिए. लोन ने कहा, मैंने अपने दिवंगत पिता से सीखा है कि राजनीति सेवा और समर्पण का एक रूप है. इसलिए, हमेशा सच्चाई की राजनीति करनी चाहिए.

> **बिलाल की आगे की योजना क्या है?**
>
> बिलाल लोन ने अभी तक यह साफ नहीं किया है कि वो पीपल्स कॉन्फ्रेंस पार्टी पर अपना दावा ठोकेंगे या नहीं. इस पार्टी की स्थापना उनके पिता और हुर्रियत के पूर्व चेयरमैन अब्दुल गनी लोन ने 1978 में की थी. अगर वह ऐसा करते हैं, तो उनका सीधा मुकाबला अपने छोटे भाई सज्जाद लोन से होगा, जो अभी पार्टी की कमान संभाले हुए हैं. हालांकि, बिलाल लोन के महबूबा मुफ्ती की पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में शामिल होने की अटकलों और अफवाहों के बीच, उन्होंने कहा कि उन्होंने अभी इसपर विचार नहीं किया है कि वो नई पार्टी बनाएंगे या किसी मौजूदा पार्टी में शामिल होंगे.

परिसीमन को लेकर फिर गरमाई राजनीति

सीटों में कटौती के डर से एकजुट हो रहा आदिवासी समाज

रांची. झारखंड में परिसीमन का भूत एक बार फिर आकार लेता दिख रहा है. आदिवासी समाज कहीं ना कहीं यह मानकर चल रहा है कि उनके हिस्से की सीटें अब पहले की तुलना में कम हो रही हैं. झारखंड में इसी कारण से समाज के लोग धीरे-धीरे आंदोलित हो रहे हैं.

आदिवासी समाज को यह बताने का प्रयास किया जा रहा है कि परिसीमन से झारखंड में लोकसभा और विधानसभा की आरक्षित सीटों की संख्या कम हो जाएगी.

दरअसल, विधानसभा और लोकसभा में सीटों की संख्या बढ़ाने को लेकर केंद्र सरकार मशक्कत कर रही है. इस क्रम में राज्य में विधानसभा सीटों की संख्या पूर्व की तुलना में डेढ़ गुना तक बढ़ने का अनुमान है. आदिवासी समुदाय का नेतृत्व कर रहे लोग चाहते हैं कि आरक्षित सीटों की संख्या भी इसी अनुपात में बढ़े. विभिन्न स्तरों पर इसके लिए जागरुकता कार्यक्रम संचालित हो रहे हैं. कांग्रेस और झामुमो से जुड़े नेता इसका नेतृत्व करते दिख रहे हैं. पूर्व मंत्री बंधु तिर्की का मानना है कि परिसीमन को नहीं रोका गया तो झारखंड में आदिवासियों को बड़ा नुकसान हो जाएगा.

उनके नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं के एक समूह ने आगामी 30 अगस्त को आदिवासी एकता महाजुटान का आह्वान भी किया है. मोरहाबादी में आयोजित इस रैली का सभी दलों के आदिवासी नेताओं को आमंत्रित करने की योजना है.

> **राजनीतिक मोर्चे पर जंग**
>
> इस मुद्दे पर झारखंड में सरकार और विपक्षी दलों की सोच लगभग एक जैसी है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस मुद्दे पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के स्टालिन की बैठक में भाग लेकर क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन मजबूत किया है. दक्षिण के राज्य पहले से इस फैसले का विरोध कर रहे हैं और तर्क दे रहे हैं कि जनसंख्या नियोजन के लिए किए गए प्रयासों के कारण दक्षिण में आदिवासी समुदाय की जनसंख्या कम हुई है. इसके एवज में आदिवासी समाज को राजनीतिक संरक्षण मिलना चाहिए.

निकाय चुनाव की जंग : बीजेपी की फॉर्मेट रणनीति

जयपुर. राजस्थान में प्रस्तावित पंचायत और निकाय चुनावों को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं. भाजपा ने अभी उम्मीदवारों के चयन की औपचारिक प्रक्रिया शुरू नहीं की है, हालांकि पार्टी ने चुनाव संचालन समिति के संभाग प्रभारियों की नियुक्ति कर तैयारियों का पहला चरण पूरा कर लिया है.

अब अगस्त के पहले सप्ताह में होने वाली प्रदेश स्तरीय बैठक के साथ भाजपा अपनी चुनावी रणनीति को अंतिम रूप देने की दिशा में कदम बढ़ाएगी. भाजपा पंचायत और निकाय चुनावों को केवल स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि चुनने का माध्यम नहीं, बल्कि प्रदेश की राजनीतिक ताकत और संगठनात्मक क्षमता का पहला बड़ा परीक्षण मान रही है. इन चुनावों के माध्यम से 2028 के विधानसभा चुनाव के लिए सत्ता रिपीट का पहला बड़ा ब्लूप्रिंट तैयार होगा. यही कारण है कि भाजपा उम्मीदवार चयन और संगठनात्मक समन्वय के जरिए चुनावी मुकाबले में उतरने की तैयारी कर रही है.

विशेष | मायावती या चंद्रशेखर, कौन किस पर भारी?

यूपी की दलित राजनीति में क्या चल रहा?

लखनऊ. यूपी में 2027 चुनाव के लिए बिसात बिछनी शुरू हो गई है. बसपा और आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) चुनावी समर में कूद गए हैं. दोनों सियासी दलों की नजर यूपी के दलित वोटरों पर हैं. मायावती सोशल मीडिया के जरिए एक्टिव होकर दलितों की आवाज बनने में जुटी हैं, तो संगठन को मजबूत करने के लिए कई कड़े कदम उठा रही हैं.

आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के प्रमुख और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद सदन से लेकर सड़क तक दलितों के मुद्दों को उठाने में लगे हैं. चंद्रशेखर ने यूपी चुनाव के लिए पहली सूची जारी करते हुए 45 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी. जिसमें 18 दलित, 16 ओबीसी, 10 मुस्लिम और 1 सिख चेहरे को मैदान में उतारा गया है. साफ है कि चंद्रशेखर यूपी में दलित वर्ग को साधने में जुट गया है.

मायावती खुद ले रही बड़े फैसले- बसपा सुप्रीमो मायावती पिछले कुछ समय से एक्टिव होकर लगातार बड़े फैसले ले रही हैं. इनमें यूपी विधानसभा चुनाव से पहले संगठन में बड़ा फेरबदल करते हुए 6 राज्यों के कोऑर्डिनेटर अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से निकाल दिया है. राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद 10 अगस्त के बाद यूपी के कुछ जिलों में होने वाले कार्यकता सम्मेलनों में हिस्सा लेंगे. हालांकि उनके कद बढ़ने को लेकर मायावती सोशल मीडिया पर स्पष्ट कर चुकी हैं कि चुनाव प्रबंधन से लेकर टिकट वितरण तक के फैसले वो खुद ले रही हैं.

सोशल मीडिया में एक्टिव- मायावती इस बार यूपी चुनाव में किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती हैं. इसके साथ ही दलित समाज के मुद्दों और घटनाओं पर मायावती लगातार सक्रिय होकर सोशल मीडिया के जरिए अपना मजबूती से पक्ष भी रख रही हैं.

> **चंद्रशेखर ने दलित उम्मीदवार उतारे**
>
> उधर आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने यूपी चुनाव को देखते हुए उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की. दलित और मुस्लिम समुदाय को प्रमुखता देकर पार्टी ने साफ संकेत दिया है कि उसका लक्ष्य अब केवल बहुजन समान पार्टी के परंपरागत बोट बैंक तक सीमित नहीं है. बल्कि वह समाजवादी पार्टी के पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) समीकरण में भी राजनीतिक सेंध की कोशिश कर रही है. राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि उम्मीदवारों का यह सामाजिक संतुलन सोची-समझी चुनावी रणनीति का हिस्सा है.